

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठाधीन अधिकारी- रॉड मल वर्मा (ज़र.प.एम.)

प्रकरण संख्या 120/2014

1. कालूराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट साकिन ग्राम सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

बनाम

1. सोहन पुत्र गणेशा जाति मेहतर निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
1/1 दुलाराम पुत्र श्री सोहन जाति मेहतर निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार ज़रिये भू-प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्थान), सूरतगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित-

1. अधिवक्ता अपीलॉट श्री राकेश कुमार मनचन्दा
2. अधिवक्ता रैस्पोंडेंट श्री भगवानदत्त शर्मा

निर्णय

दिनांक: 12.12.2017

1. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा एक 11 जीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के प.न. 201/82 किला न. 1 ता 25/8.200 है 0 अ.का., प.न. 201/54 के किला न. 3/1/0.128, 4 ता 8/1.285, 13 ता 18/1.518, 23 ता 25/0.759 = 3.688 है 0 अ.क.व. प.न. 201/55 के किला न. 5/0.101 है 0 अ.क. कुल 9969 है 0 अ.क. कृषि भूमि सोहन पुत्र गणेशा जाति मेहतर साकिन सूरतगढ़ के नाम से नामांतरण संख्या 168 दिनांक 24.9.2014 दर्ज किया है। विवादित भूमि पर अपीलॉट का दशक वर्षों पर कब्जा बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा था। जिसकी मौका जांच किये बिना ही अपीलॉटने आदेश जारी कर दिये। विवादित भूमि को अपने नाम से रिकार्ड में ना करवाने बावत स्वयं मृतक सोहनलाल के पुत्र दुलाराम के द्वारा एक प्रार्थना मय शपथ पत्र उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 27.8.2012 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट मांगी गई थी। तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा अपीलॉट कालूराम पुत्र अर्जुनराम जाट एवं शंकरलाल पुत्र शेराराम जाट का मौका पर कब्जा होना तथा कब्जा नियमन की पत्रावली आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ के कार्यालय में जैरकार होने और रकबा विवादित होने के कारण प्रार्थी ने कब्जा ना लेने का अंकन किया गया है। आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांक 10 दिनांक 04.01.2013 के प्रार्थना पत्र नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश दे दिये।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र 120/14 पर दर्ज की जाकर प्रार्थीगण को ज़रिये सम्मन तलब किया गया। अपीलॉट की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये। रैस्पोंडेंट तरफ से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलॉट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मीमा ही मेरी बहस है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलॉट का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। नियमन की पत्रावली भी सक्षम न्यायालय में जैरकार है। सोहन वल्द गणेशा का वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। उक्त वर्णित नामांतरण एक मृतक व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। जो कि नियमानुसार गलत एवं विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलॉट स्वीकार की जावे। वकील रैस्पोंडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलॉट ने धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम के तहत यह अपील पेश की है। धारा 75 में मूल आदेश के विरुद्ध ही अपील पेश की जा सकती है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के आदेश की पालना में ही विवादित इंतकाल दर्ज किया है। अतः इसी बिन्दु पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलॉट ने यह नहीं बताया कि वे विवादित भूमि पर किस हैसियत से काबिज है। इनका विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। न ही उक्त रकबा इन्हे आवंटित हुआ है। उक्त भूमि रकबा राज में से हमें मिली है। अपीलॉट द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। अपीलॉट अतिक्रमी है। अतः उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाकर कब्जा हमें दिलावे एवं अपील अपीलॉट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, गणन, चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 168

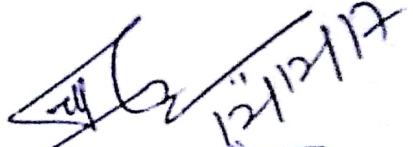
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़
कोड संख्या-4975

86

दिनांक 24.9.2014 के विरुद्ध यह अपील पेश की है। परन्तु पत्रावली में सलंगन दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार द्वारा विवादित इंतकाल स्वीकृत करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई कौताही नहीं बरती गई है। न ही नियमविरुद्ध यह इंतकाल स्वीकृत हुआ है। जब तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा 24.9.2014 को सोहन बल्द गणेशा जाति मेहतर के नाम से विवादित रकबा का इंतकाल स्वीकृत हो चुका था तो अपीलांट द्वारा विवादित रकबा पर कब्जा-काश्त करना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि कब्जा किस हैसियत से किया है। न ही अपनी बहस में इस संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत किया।

उपरोक्त तथ्यों से यह सिद्ध है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 168 दिनांक 24.9.2014 सही स्वीकृत किया गया है। तथा अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से जबरन कब्जा किया हुआ है। चूंकि रेस्पोंडेंट खातेदार कृषक है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 24.9.2014 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यदि खातेदार कृषक के खातेदारी हकूकों, कब्जे में कोई दखल करें तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैलस शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला फ़ैलक्टर
कोड सूरतगढ़ 8975